बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 112

एनबीएफसी में सुधार

वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) के ताजातरीन आंकड़े गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (एनबीएफसी) में मंदी के स्तर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अगर आवास वित्त कंपनियों को अलग कर दिया जाए तो एनबीएफसी द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में मंजूर ऋण में सालाना आधार पर 31 फीसदी की गिरावट आई है। समान वर्ष की तीसरी तिमाही में इसमें सालाना आधार पर 17 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी। यह वह अवधि है जिस दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज यानी आईएलऐंडएफएस तथा उससे जुड़ी संस्थाओं के डिफॉल्ट की खबरें आने के बाद एनबीएफसी बाजार हिला हुआ था और निवेशकों का विश्वास डोला हुआ था। इस क्षेत्र में नकदी का संकट चिंता का विषय बन गया था क्योंकि एनबीएफसी को फंड की कमी अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक थी और वृद्धि की संभावनाओं को धक्का पहुंचा रही थी। यह मानने की कोई खास वजह नहीं है कि वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में एनबीएफसी के लिए हालात बेहतर हुए होंगे।

एफआईडीसी के आंकड़ों का और बारीक अध्ययन बताता है कि सबसे बड़ी दिक्कत एनबीएफसी द्वारा लंबी अवधि के ऋण देने में आ रही है। जनवरी से मार्च तिमाही के बीच इसमें सालाना आधार पर 77 फीसदी की गिरावट आई। इसमें चकित होने वाली बात नहीं है क्योंकि परिपक्वता अवधि में अंतर यानी बैंकों से अल्पावधि का ऋण लेकर लंबी अवधि की परियोजना को फंड करना, आईएलऐंडएफएस तथा अन्य एनबीएफसी के समक्ष बड़ा संकट बना हुआ था। इसका वृद्धि और रोजगार की स्थिति पर बड़ा असर होना लाजिमी है। वृद्धि में सतत बढ़ोतरी के लिए यह आवश्यक है कि परियोजनाओं को सुगमता से वित्तीय सहायता हासिल होती रहे तथा रोजगार निर्माण की गति बरकरार रहे। अकुशल श्रमिक बुनियादी ढांचा और विनिर्माण उद्योग पर खासतौर पर निर्भर रहते हैं। सरकारी बैंकों की अत्यधिक जोखिम वाली बैलेंस शीट के कारण एनबीएफसी बुनियादी परियोजनाओं को ऋण देने वाली बिचौलिया संस्थाओं के रूप में सामने आईं। परंतु इस क्षेत्र में व्याप्त संकट ने इसके संसाधन सोख लिए। म्युचुअल फंड के निवेशकों ने भी इससे दूरी बना ली।

अब, भले ही बैंकों में सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं लेकिन वे अभी तक एनबीएफसी का स्थान नहीं ले सके हैं। न ही उन्होंने एनबीएफसी को कर्ज देना शुरू किया है। पुनर्भुगतान की चिंता के कारण एनबीएफसी की फंडिंग की लागत कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। एनबीएफसी के पांच वर्ष के शीर्ष बॉन्ड की लागत गत वर्ष 70 आधार अंक बढ़ गई। यही कारण है कि एनबीएफसी ने रिजर्व बैंक से कहा था कि उनके लिए एक अलग ऋण व्यवस्था आवश्यक है। हालांकि रिजर्व बैंक इसका इच्छुक नहीं दिखा और उसके पास इसकी जायज वजह भी हैं। असहज तरीके से विस्तार कर चुके एनबीएफसी क्षेत्र की साफ-सफाई आवश्यक है। इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि यह संकट व्यवस्थित नहीं है और केवल कुछ ही एनबीएफसी ने अचल संपत्ति क्षेत्र को यूं गड़बड़ी करके ऋण दिया है और केवल उनकी ही हालत खराब है। कुछ अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि एनबीएफसी की हालत के बारे में सूचनाओं का अभाव है और शायद परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा से भी इनकी हालत सुधर सकती है। बैंकों के साथ ऐसा किया जा चुका है। बहुत संभव है कि ऐसा करने से अच्छी एनबीएफसी में निवेशकों का यकीन बहाल हो जाए और खराब एनबीएफसी को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। इसके अलावा आरबीआई को एक व्यापक कार्य योजना पेश करनी चाहिए। आरबीआई के लिए जरूरी यह है कि वह ऐसा तरीका खोजे जो इस क्षेत्र की सेहत दुरुस्त करने के अलावा बड़ी एनबीएफसी के नियमन में भी कड़ाई ला सके।

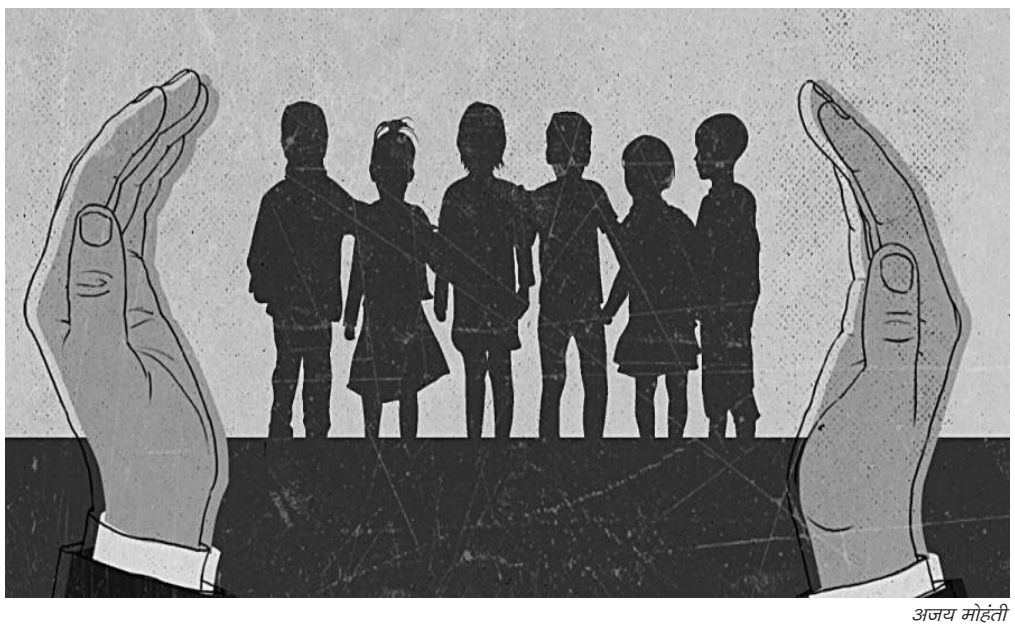

अजय मोहंती

बाल विकास सुधारों की रफ्तार बढ़ाने की दरकार

भारत बच्चों की स्थिति सुधारने में प्रगति कर रहा है, लेकिन कुछ संकेतक स्थिर बने हुए हैं। भारत को वैश्विक रैंकिंग सुधारने के लिए तेजी से सुधार लाना होगा। बता रहे हैं पार्थसारथि शोम

दुनियाभर में करीब 70 करोड़ बच्चे बचपन का अनुभव लेने या इसके खत्म होने से पहले ही वयस्क हो जाते हैं। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले एक गैर-लाभकारी संगठन- सेव दी चाइल्ड ने अपनी 2019 की रिपोर्ट जारी की है। संगठन ने विश्व बैंक, यूनेस्को, वैश्विक आबादी के लिए संयुक्त राष्ट्र के अन्य कार्यालयों, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि से आंकड़े जुटाए हैं। इसने देश भर बच्चों की स्थिति को लेकर बहस छेड़ दी है।

समय से पहले बचपन खत्म होने के आकलन के मापदंड में आठ संकेतक शामिल हैं। ये संकेतक पांच साल से पहले मृत्यु (प्रति 1,000 जीवित जन्म), कुपोषण से कम लंबाई (0 से 59 महीनों के बच्चों का प्रतिशत), प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से वंचित होना (5 से 17 साल की आयु के बच्चों का प्रतिशत), बाल श्रमिकों के वयस्कों के काम करना (5 से 17 साल की आयु का प्रतिशत), प्रति 1,000 लड़कियों पर विवाहित लड़कियां या किशोरावस्था मां बनना (दोनों 15 से 19 वर्ष की लड़कियों के लिए) और हिंसा से विस्थापन या नरसंहार के शिकार (0 से 19 वर्ष की आयु में प्रति एक लाख पर मृत्यु) हैं।

हम भारत के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए आठ तुलना करने लायक देशों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमने दो सवाल रखे हैं- 1. वर्तमान स्कोर क्या है? 2. स्कोर में कितना सुधार हुआ है? सारणी 1 कुछ अच्छी खबरों से शुरू होती है। अधिकतम 1,000 के स्कोर में भारत का 2019 में स्कोर 769 रहा। यह बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से अधिक था, लेकिन चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और श्रीलंका से कम था। केवल चीन और श्रीलंका का स्कोर ही 900 से अधिक रहा। इस स्कोर के निर्धारण को व्यापक रूप में देखने की जरूरत है। आठ संकेतकों में से हरेक को अलग-अलग तरीके से मापा गया है, इसलिए इसे 'सामान्य' बनाया जाना चाहिए या इसका एक मापक तय किया जाना चाहिए। इस तरह एक सामान्यीकृत संकेतक मूल्य एक्सएन (एक्स - एल)/(एच - एल) के बराबर है। यहां एक्स किसी देश का उस संकेतक2 के लिए वास्तविक मूल्य है, एल (सबसे खराब) सभी देशों में संकेतक के लिए सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मूल्य है और एच (सबसे बेहतर) सूचकांक के लिए सबसे कम देखे जाने वाला मूल्य है। किसी देश के कुल स्कोर का आकलन सभी आठ संकेतकों के एक्सएन को जोड़कर, इस योग को आठ से विभाजित कर और फिर 1,000 से गुणा करके किया जाता है ताकि आंकड़े 0 से 1000 के बीच प्राप्त हों।

भारत का वर्तमान स्कोर वर्ष 2000-2019 के दौरान 137 अंकों के सुधार को दर्शाता है, जो 632 से बढ़कर 769 पर पहुंच गया। यह सुधार बांग्लादेश और नेपाल के सुधार से कम रहा। हालांकि वे भारत के स्कोर तक नहीं पहुंच पाए। चीन और श्रीलंका का स्कोर पहले ही काफी ऊपर है, इसलिए वे निस्संदेह बहुत अधिक सुधार दर्ज नहीं कर पाए। ब्राजील का सुधार भी तुलनात्मक रूप से कम रहा। इंडोनेशिया और पाकिस्तान में भी सुधार कमजोर रहा। विभिन्न देशों को मिले इन स्कोरों से उन्हें क्रमबद्ध किया जा सकता है। वर्ष 2019 के लिए भारत की रैंकिंग 176 देशों में 113वीं रही।

सारणी 2 पूरी तस्वीर को चुनिंदा संकेतक घटकों में तोड़ती है। इस तरह भारत में 2015-2017 के दौरान बाल मृत्यु की दर में गिरावट दर्ज की गई, जो नमूने में शामिल अन्य देशों के समान थी। लेकिन लंबी अवधि 2011-18 के दौरान भारत गंभीर कुपोषण (कम लंबाई) को कम करने में कोई सुधार दर्ज नहीं कर सका, जबकि इस पैमाने पर श्रीलंका और पाकिस्तान में हालात और बिगड़े हैं। विशेष रूप से श्रीलंका में हालात बदतर होना आश्चर्यजनक है। साफ तौर पर स्कूल न जाने वाले बच्चों का भारत का संकेतक 2011 से 2018 के दौरान बदतर हुआ है। यह इसलिए बहुत चिंताजनक है क्योंकि इस स्तर पर नमूने में शामिल हर देश और वैश्विक औसत में सुधार आया है।

सारणी 3 उस चीज पर केंद्रित है, जिसे मैं 'बाल-वयस्क' संकेतक कहना चाहूंगा। भारत में बाल श्रम को घटाने में कोई सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश और इंडोनेशिया में भी बाल श्रम को घटाने के स्तर पर कोई प्रगति नहीं हुई। हालांकि ब्राजील और श्रीलंका ने सुधार दर्ज किया है।

भारत ने 2011-18 के दौरान चीज क्षेत्र में शानदार प्रगति की है, वह बाल विवाह है। हालांकि अन्य देशों की तस्वीर मिलीजुली है। इस स्तर पर बांग्लादेश और श्रीलंका में सुधार हुआ है। इस मामले में चीन और पूर्ववत स्तर पर हैं। हालांकि चीन इस पैमाने पर पहले ही काफी ऊपर है। वहीं नेपाल, पाकिस्तान और ब्राजील में बाल विवाह के पैमाने पर हालात बदतर हुए हैं। वास्तव में ब्राजील की इस पैमाने पर स्थिति खराब होना आश्चर्यजनक है। संभवतया यह गलती की वजह से हो सकता है। किशोरावस्था में मां बनने के पैमाने पर भारत का 2016 का स्कोर चीन और श्रीलंका को छोड़कर नमूने में शामिल अन्य देशों से काफी बेहतर रहा है। भारत की यह उपलब्धि गौर करने लायक है।

अंतिम संकेतक बाल मृत्यु दर से संबंधित है। भारत इस पैमाने पर चीन और श्रीलंका के ठीक पीछे है। यह गरीबी के बावजूद अच्छा स्कोर है। इस स्तर पर ब्राजील की हालत काफी खराब है। कुल मिलाकर भारत बच्चों की स्थिति सुधारने में प्रगति कर रहा है, लेकिन कुछ संकेतक स्थिर बने हुए हैं। भारत को अपनी वैश्विक रैंकिंग सुधारने के लिए तेजी से सुधार लाना होगा। एक अन्य निष्कर्ष यह है कि हिंसाग्रस्त क्षेत्र के रूप में ब्राजील की छवि सही साबित होती नजर आती है। मैं फिर इस बात पर जोर दूंगा कि शुद्ध आर्थिक संकेतक तब तक निरर्थक हैं, जब तक उनमें सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को शामिल नहीं किया जाता है। यह भारत से अधिक प्रासंगिक और कहीं नहीं हो सकता।

सारणी 1: बचपन: रैंक और स्कोर

देश	रैंक 2019 (176 देशों में)	स्कोर (1-1000) 2000	स्कोर (1-1000) 2019	स्कोर में बदलाव (2000-19)
चीन	36	861	941	80
बांग्लादेश	127	575	728	153
ब्राजील	99	785	806	21
भारत	113	632	769	137
इंडोनेशिया	107	721	792	71
नेपाल	134	543	685	142
पाकिस्तान	149	540	626	86
श्रीलंका	56	867	915	48

स्रोतः ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट, 2017 और 2019, सेव द चिल्ड्रन

सारणी 2: बच्चे: चुनिंदा संकेतक

देश	बाल मृत्यु दर 2015	बाल मृत्यु दर 2017	गंभीर कुपोषण 2011-16	गंभीर कुपोषण 2013-18	स्कूल से बाहर 2011-16	स्कूल से बाहर 2013-18
चीन	10.7	9.3	9.4	8.1	11.6	7.6
बांग्लादेश	37.6	32.4	36.1	36.1	28.0	17.4
ब्राजील	16.4	14.8	7.1	7.1	7.3	7.2
भारत	47.7	39.4	38.7	38.4	18.6	20.2
इंडोनेशिया	27.2	25.4	36.4	36.4	14.3	14.2
नेपाल	35.8	33.7	37.4	35.8	13.4	13.8
पाकिस्तान	81.1	74.9	45.0	47.2	42.9	40.8
श्रीलंका	9.8	8.8	14.7	17.3	10.1	6.4
विश्व	42.5	39.1	23.2	22.2	17.8	17.6

स्रोतः ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट, 2017 और 2019, सेव द चिल्ड्रन

सारणी 3: वयस्कों की तरह बच्चे: चुनिंदा संकेतक

देश	कामकाजी जीवन शुरू 2011-16	कामकाजी जीवन शुरू 2013-18	शादी 2011-16	मां बनी बच्चियां 2013-18	अत्यधिक हिंसा के शिकार 2016	अत्यधिक हिंसा के शिकार 2016
चीन	....	....	3.1	3.1	6.5	0.6
बांग्लादेश	4.3	4.3	44.2	32.4	84.4	1.5
ब्राजील	8.1	6.6	3.9	15.1	62.7	17.7
भारत	11.8	11.8	21.1	15.2	24.5	1.3
इंडोनेशिया	6.9	6.9	12.8	12.8	48.0	2.8
नेपाल	37.4	37.4	24.2	27.1	62.1	1.5
पाकिस्तान	....	.....	13.1	13.5	37.7	6.5
श्रीलंका	2.5	1.0	9.0	6.0	14.8	0.8
विश्व	12.6	12.6	14.4	16.0	50.4	3.3

राजनीतिक रूप से उदार आर्थिक रूप से अनुदार

सम सामयिक

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

राजनीति को हां, अर्थशास्त्र को ना?

चंद रोज पहले चेन्नई से प्रकाशित होने वाले और देश के शीर्षस्थ समाचार पत्रों में स्थान रखने वाले एक अखबार में भारत के भविष्य को लेकर एक निराशावादी आलेख प्रकाशित हुआ। उस आलेख में जताए गए अनुमान अत्यंत भयानक थे। उसे लिखा था हर्ष मंदर सिंह ने, जो कभी प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे लेकिन अब पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुके हैं। वह हमेशा से सरकार के कटु आलोचक रहे हैं, भले ही किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता रही हो। अपनी इस आलोचना में वह अक्सर नैतिक और व्यावहारिक आधार पर सही भी होते हैं।

बहरहाल, उनका यह आलेख इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त विजय के बाद नेहरूवादी उदारवादियों के मन में निराशा घर कर गई है। उनके लिए तो मानो दुनिया खत्म ही हो गई है।

बहुत अजीब संयोग है कि लगभग उसी समय कराची से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डॉन में भी एक आलेख प्रकाशित हुआ जिसे लिखा था जाने माने पाकिस्तानी अर्थशास्त्री अंजुम अल्ताफ ने। भारतीय लेखक की तरह उन्होंने भी भारतीय उदारवादियों की निराशा को ही प्रकट किया। वह कहते हैं कि नेहरूवादी योजना एक बुर्जुआ योजना थी जिसमें काले अंग्रेजों का एक छोटा सा समूह भारत पर ब्रिटिश राजनीतिक मूल्य थोपने का प्रयास कर रहा था। वह बेस्ट सेलर पुस्तक आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक सुनील खिलनानी को उद्धृत करते हैं।

खिलनानी ने लिखा था कि सन 1947 में अधिकांश भारतीयों को यह पता ही नहीं था कि उन्हें क्या सौंपा गया है। इसलिए नेहरू और उनके वंशजों ने बड़ी मशक्कत करके उन्हें समझाया कि धार्मिक सहिष्णुता, उदार मूल्य और राष्ट्रीय मामलों के संचालन का उच्च वर्गीय लेकिन उदार अंग्रेजी दां माहौल ही वे चीजें हैं जो उन्हें विरासत में मिलीं।

अल्ताफ कहते हैं कि यह सब इतिहास की बात हो चुकी है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता और तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों के परदे के पीछे भारतीय मूलत: असहिष्णु और अलोकतांत्रिक हैं।

ऐसे विचार प्रकट करने वाले विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की पूरी की पूरी जमात है। अर्मत्य सेन जैसे लोग भी इसमें शामिल हैं, जिनकी विद्वता पर किसी को संदेह नहीं है लेकिन उनकी आशंकाएं और उनके द्वारा की जा रही व्याख्याएं यकीनन संदेह के घेरे में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी विचार अच्छा है या बुरा, इसका निर्धारण इस बात से नहीं होता है कि उक्त विचार किसने प्रकट किया है। ऐसे में यह दुखद है कि अधिकांश उदारवादी लोग ऐसे ही सोचते हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं: राजनीतिक उदारवाद, आर्थिक उदारवाद के साथ किस तरह सुसंगत है? मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि सन 1950 के बाद से संविधान के अनुच्छेद 19(जी) का बहुत हद तक मर्दन हुआ है। यह हर नागरिक को अपनी पसंद का रोजगार जैसे चाहे वैसे करने की स्वतंत्रता देता है।

वाम उदारवादियों का उत्तर हमेशा यही रहा है कि अगर आर्थिक उदारीकरण का अर्थ राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी और आर्थिक गतिविधि में निरंतर हस्तक्षेप से है तो यह आवश्यक है कि इसके माध्यम से समतावादी आर्थिक लक्ष्यों और गरीबी उन्मूलन जैसे लक्ष्यों को हासिल किया जाए। क्या वाकई?

ऐसी स्थिति में क्या हमें इसका उलट सवाल नहीं पूछना चाहिए? मसलन क्या राजनीतिक उदारवाद को अर्थव्यवस्था के समतावादी निष्कर्षों के साथ असंगत होना चाहिए। आखिर कार तमाम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी पहले चीन का राजनीतिक उदारवाद ऐसे समतावादी आर्थिक नतीजे देने में कामयाब रहा जिन्हें वाम उदारवादी पसंद करते हैं। ऐसे में जो लोग नेहरूवादी राजनीतिक उदारवाद की उचित सराहना करते हैं वे नेहरूवादी आर्थिक उदारवाद की अनदेखी कर गलत करते हैं। नेहरू के युग के किसी भी आर्थिक विधान को देखिए, आप पाएंगे कि उसमें उदारीकरण की भावना निहित है।

यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी कार की तरह हो गई जिसके एक ओर राजनीतिक उदारवाद रूपी कार के पहिये जबकि दूसरी ओर आर्थिक उदारवाद के रूप में स्कूटर के पहिये लगा दिए गए हैं। जाहिर है इसका संतुलन खराब रहेगा। विडंबना यह है कि जो उदारवादी इन दिनों नेहरूवादी राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के गुजर जाने से नाराज हैं, वही उनके दुर्लभ आर्थिक उदारवाद को समाप्त करने की भी मांग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए डॉ मनमोहन सिंह तक ने समय-समय पर कहा है कि भारतीय श्रम बाजार को अधिक लचीला बनाए जाने की आवश्यकता है। इससे उनका तात्पर्य कम उदार बनाने से ही है।

इसी प्रकार वही लोग जो वर्ष 2006 में मनरेगा लाए उन्होंने गरीबों की सब्सिडी खत्म किए जाने की बात पर कोई सवाल नहीं उठाया। वाम उदारवादी मस्तिष्क में हर चरण पर भ्रम नजर आता है। दो राय नहीं कि ऐसे लोग बेहद सदाशयता से भरे होते हैं लेकिन उनको नेहरूवादी युग से उदाहरण और उल्लेख लेने बंद करने होंगे।

मैं उनके सामने एक ऐसा मॉडल पेश कर सकता हूं जिसका अनुकरण किया जा सकता है। यह उदाहरण है सन 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध की ब्रिटिश लेबर पार्टी के न्यू लेबर का। नेहरूवादी उदार लोग भी नव उदारवादी हो सकते हैं। उन्हें राजनीतिक उदारवाद और आर्थिक उदारवाद में एक संतुलन कायम करना होगा। इसके लिए राजनीतिक उदारवाद को संकुचित करते हुए आर्थिक उदारवाद का विस्तार करना होगा। यह खेद की बात है कि राहुल गांधी ने मुझसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं ली। अगर वह लेते तो मैं उन्हें बताता कि भाजपा एकदम यही करने का प्रयास कर रही है और ऐसा करके वह एकबार फिर जीत हासिल करने जा रही है।

कानाफूसी

बाबा की मांगें

मध्य प्रदेश के स्वयंभू बाबा नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कुछ अरसा पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी न्यास का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बाबा ने सरकार से एक हेलीकॉप्टर की मांग की थी ताकि वह नर्मदा नदी के तटवर्ती इलाकों में हो रही गतिविधियों पर नजर रख सकें। उनकी इस मांग से पहले तो सरकार हक्कीबक्की रह गई लेकिन बाद में इसे ठुकरा दिया गया। अब बाबा एक नई मांग के साथ सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें मंत्रालय में एक कक्ष के साथ-साथ एक ड्रोन कैमरा मुहैया कराया जाए ताकि वह नर्मदा तथा अन्य नदियों में अवैध रेत खनन पर नजर रख सकें। इस बार उनकी दलील है कि प्रदेश की नदियों को बचाए रखने के लिए उन्हें आधुनिक अस्त्र-शस्त्र की आवश्यकता है।

वोट बैंक की जुगत

भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच की कड़वाहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के एक कदम से आग और भड़कने का खतरा उत्पन्न हो गया है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता के कुछ प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर ममता के भाषणों का प्रसारण शुरू किया गया है जिनमें वह मोदी की आलोचना करती नजर आती हैं। ऐसी स्क्रीन दक्षिणेश्वर, सोनागाछी और हजारा क्रॉसिंग जैसी जगहों पर लगाई गई हैं जहां कम आय वर्ग वाले लोग अधिक संख्या में रहते हैं। यह तृणमूल कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक भी है। दरअसल भाजपा ने इन क्षेत्रों में पार्टी के वोट बैंक में जमकर सेंध लगाई है। सूत्रों की मानें तो यह उस विश्लेषक की सलाह हो सकती है जिससे ममता हाल ही में मिलीं।

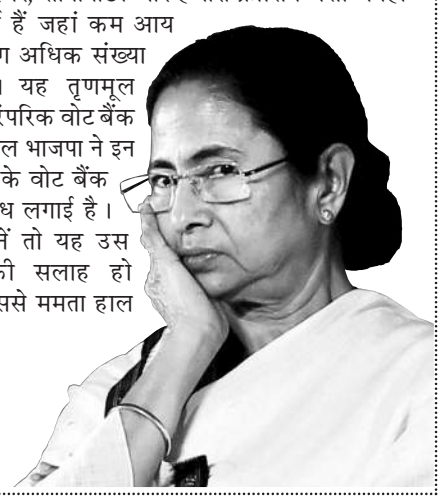

आपका पक्ष

स्वास्थ्य क्षेत्र में खराब प्रदर्शन

नीति आयोग ने हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है जिसमें उत्तर प्रदेश ने लगातार दूसरी बार सबसे खराब प्रदर्शन किया है। साल 2017 की रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर था और इस बार भी वह सबसे निचले पायदान पर रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में कई योजनाएं चला रही है लेकिन लगता है राज्य के स्वास्थ्य पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में जन्म के समय कम वजन, टीबी के इलाज की सफलता दर और जन्म के समय पंजीकरण का स्तर रैंकिंग में गिरावट के मुख्य कारण रहे। हालांकि बिहार की स्थिति भी काफी खराब है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते इन्सेफेलाइटिस वायरस से कई बच्चों की मौत होने वाले राज्य बिहार की रैंकिंग में स्थिति इस बार भी नहीं बदली और रैंकिंग में नीचे से दूसरा स्थान मिला है। यह दोनों राज्यों के लिए अच्छी स्थिति बिल्कुल नहीं कही जा सकती। इस सूचकांक की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लिए जारी की जाने वाली राशि का एक हिस्सा इस सूचकांक में राज्यों के प्रदर्शन से जोड़ने का निर्णय लिया है। हालांकि कुछ राज्यों ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। हरियाणा, राजस्थान और झारखंड इन्क्रीमेंटल परफॉर्मेंस (प्रदर्शन सुधारने की दर) के आधार पर शीर्ष तीन राज्यों की सूची में रहे। यह सूचकांक ऐसे समय में आया है जब बिहार में चमकी बुखार से कई सौ बच्चों की मौत हो गई है और प्रशासन की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। राज्यों को इस समस्या के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होंगी तो राज्य में श्रम बल की कमी होगी और आर्थिक नुकसान भी होगा। आम जनता के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए राज्य सरकारों को ठोस कदम उठाने होंगे।

तमन्ना सिंह, लखनऊ

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उप्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल स्थिति में हैं

बैंकों के एनपीए में राहत का अनुमान

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में बैंकों के एनपीए में गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अंत तक एनपीए 350 आधार अंकों की गिरावट के साथ 8 प्रतिशत पर आ सकता है। इससे पहले बैंकों में सकल एनपीए का स्तर मार्च 2018 में बकाया कर्ज के 11.5 फीसदी था जो मार्च 2019 में घटकर 9.3 फीसदी पर आ गया। एजेंसी के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए मार्च 2018 के 14.6 फीसदी के स्तर से 4 फीसदी कम होकर मार्च 2020 तक 10.6 फीसदी पर आ जाने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फंसे कर्ज के मामलों में कमी पिछले वित्त वर्ष से देखी जा रही है। ताजा एनपीए वित्त वर्ष 2018-19 में आधा होकर 3.7 फीसदी पर आ गया जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 7.4 फीसदी था। वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में इसके 3.2 फीसदी पर आ जाने का अनुमान है। सालों से बैंकों के सामने एनपीए बड़ी समस्या रही है। केंद्रीय बैंक आरबीआई लगातार इसपर नजर बनाए हुए है और कई ठोस कदम उठा रहा है। एनपीए में गिरावट को बैंकों के लिए सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा सकता है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।